

परिशिष्ट - 4

शब्दावली

क्र.सं.	शर्तें	विवरण
1.	राज्य कार्यान्वयन एजेंसी	राज्य कार्यान्वयन एजेंसी में गैर-सरकारी संगठन सहित कोई भी संगठन/संस्थाएं शामिल हैं जो राज्य सरकार द्वारा राज्य में विशिष्ट कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार से निधियां प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत हैं, जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए एसएसए और राज्य स्वास्थ्य मिशन के लिए राज्य कार्यान्वयन सोसायटी आदि।
2.	जीएसडीपी	जीएसडीपी को राज्य की कुल आय या श्रम का उपयोग करके उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य और वर्तमान मूल्यों पर उत्पादन के अन्य सभी कारकों के रूप में परिभाषित किया गया है।
3	अधिक्य अनुपात	अधिक्य अनुपात आधार चर में दिए गए परिवर्तन के संबंध में राजकोषीय चर की लोच या प्रतिक्रिया की डिग्री को इंगित करता है। उदाहरण के लिए, 0.6 पर राजस्व उछाल का अर्थ है कि राजस्व प्राप्तियों में 0.6 प्रतिशत अंक की वृद्धि होती है, यदि जीएसडीपी एक प्रतिशत बढ़ जाती है।
4	आंतरिक ऋण	राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएस) को जारी किए गए मुख्य रूप से बाजार ऋण और विशेष प्रतिभूतियों को शामिल करना।
5.	कोर सार्वजनिक और योग्यता माल	मूल सार्वजनिक वस्तुएँ वे वस्तुएँ होती हैं, जिनको सभी नागरिक एक समान रूप में उपभोग करते हैं, इस अर्थ में कि प्रत्येक द्वारा ऐसी वस्तु का उपभोग करना, किसी दूसरे के द्वारा उसी वस्तु का उपभोग करना कमी का कारण न बने जैसे कानून व व्यवस्था का प्रवर्तन, हमारे अधिकारों

		<p>की सुरक्षा तथा संरक्षण, प्रदूषण रहित हवा तथा पर्यावरणीय वस्तुएँ और सड़क जैसी आधारिक अवसंरचना आदि। मेरिट गुड्स आधारित वे वस्तुएँ होती हैं जो लोक क्षेत्रों में निशुल्क या रियायती दरों पर उपलब्ध कराई जाती हैं क्योंकि योग्यता या सरकार को भुगतान करने की इच्छा की बजाय उन वस्तुओं की, जरूरत की कुछ अवधारणाओं के आधार पर, प्रत्येक को या पूरे समाज को उनकी आवश्यकता होती है। इसलिए ऐसी वस्तुओं के उपभोग करने के लिए प्रेरित किया जाता है। ऐसी वस्तुओं के उदाहरण में गरीबों को पोषित करने हेतु निशुल्क प्रावधान या रियायती दरों पर भोजन उपलब्ध करवाना, उनके जीवन स्तर की गुणवत्ता को बेहतर बनाने हेतु स्वास्थ्य सेवाओं की आपूर्ति तथा रुग्णता को कम करना, सभी को बुनियादी शिक्षा मुहैया करवाना, तथा पेयजल तथा साफ-सफाई आदि को शामिल किया जाता है।</p>
6	विकास व्यय	<p>व्यय के आंकड़ों का विश्लेषण, विकास और गैर-विकास व्यय में अलग-अलग होता है। राजस्व लेखा, पूंजीगत परिव्यय तथा ऋणों एवं अग्रिमों से संबंधित सभी व्यय, सामाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं तथा सामान्य सेवाओं के तहत श्रेणीबद्ध है। मोटे तौर पर, सामाजिक व आर्थिक सेवाएँ विकास व्यय से बनी होती हैं, जबकि सामान्य सेवाओं पर व्यय को गैर-विकास व्यय के रूप में माना जाता है।</p>
7.	ऋण स्थिरता	<p>ऋण स्थिरता समय की अवधि में एक वर्तमान ऋण सकल घरेलू उत्पाद अनुपात बनाए रखने के लिए राज्य की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है और यह भी अपने ऋण सेवा करने की क्षमता के बारे में चिंता का प्रतीक। इसलिए, ऋण की स्थिरता वर्तमान या प्रतिबद्ध दायित्वों को पूरा करने के लिए तरल परिसंपत्तियों की</p>

		पर्याप्तता और ऐसे उधारों से रिटर्न के साथ अतिरिक्त उधारों की लागतों के बीच संतुलन बनाए रखने की क्षमता को भी संदर्भित करती है। इसका अर्थ है कि राजकोषीय घाटे में वृद्धि ऋण की सेवा करने की क्षमता में वृद्धि से मेल खाती है।
8	गैर-ऋण की पर्याप्तता प्राप्तियाँ (संसाधन गैप)	वृद्धिशील ब्याज देनदारियों और वृद्धिशील प्राथमिक व्यय को कवर करने के लिए राज्य की वृद्धिशील गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता। यदि वृद्धिशील गैर-ऋण प्राप्तियाँ वृद्धिशील ब्याज बोझ और वृद्धिशील प्राथमिक व्यय को पूरा कर सकती हैं तो ऋण स्थिरता को काफी सुविधाजनक बनाया जा सकता है।
9	उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता	कुल ऋण प्राप्तियों के लिए ऋण मोचन (मूल + ब्याज भुगतान) के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है और यह इंगित करता है कि ऋण मोचन में ऋण प्राप्तियों का उपयोग किस हद तक किया जाता है जो उधार प्राप्त निधियों की शुद्ध उपलब्धता को दर्शाता है।
10	गैर ऋण प्राप्तियाँ	वृद्धिशील ब्याज देनदारियों और वृद्धिशील प्राथमिक व्यय को कवर करने के लिए राज्य की वृद्धिशील गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता। यदि वृद्धिशील गैर-ऋण प्राप्तियाँ वृद्धिशील ब्याज बोझ और वृद्धिशील प्राथमिक व्यय को पूरा कर सकती हैं तो ऋण स्थिरता को काफी सुविधाजनक बनाया जा सकता है।
11	शुद्ध ऋण उपलब्ध	सार्वजनिक ऋण चुकोती पर सार्वजनिक ऋण प्राप्तियों की अधिकता और सार्वजनिक ऋण पर ब्याज भुगतान।